worked out, for 1997-98, the first full year of BMS implementation.

**Grassroot Planning in States**

1826. SHRI W. ANGOU SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) how far the Central Planning Department has taken up implementation of the concept of grassroot planning in States;

(b) whether this concept of grassroot planning can be reflected in the preparation of the Ninth Five Year Plan; and

(c) whether the Planning Commission has prepared the Ninth Five Year Plan with the spirit of the 73rd and 74th Constitution (Amendment) Acts, to devolve financial powers at the grassroot level of the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRIMATI RATNAMALA DEHARESHWAR SAVANOOR): (a) to (c) The setting of Panchayati Raj Institutions (PRIs) consequent to the 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts marks a watershed with implementation of the concept of grassroot planning in the states. As a consequence of these Acts, State Governments have enacted enabling legislations providing for elected bodies at the village, intermediate and district level with adequate representation from the weaker sections and women. All the states have constituted State Finance Commissions and State Election Commisssions. The Approach Paper to the Ninth Plan especially outlines the role of PRIs in decentralised planning. The formulation of the Ninth Five year Plan is still underway in the Planning Commission. However, financial devolution to PRIs—have already been initiated. Funds for Jawahar Rojgar Yojana are directly going to PRIs in the ratio of 65:15:20 for Gram Panchayat, intermediate Panchayat and Zilla Parishad respectively.

**बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या**

1827. **श्री गोपाल सिंह जी॰ सोलंकी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में विभिन्न राज्यों में कुल कितने व्यक्ति बेरोजगार थे;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में निजी तथा सरकारी क्षेत्र में अनुमानतः कितने रोजगार सृजित किए गए;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में बेरोजगार व्यक्तियों की अनुमानित संख्या कितनी है; और

(घ) क्या गुजरात राज्य में जहां निजी क्षेत्र में कम रोजगार के अवसर सृजित हुए है, रोजगार बढ़ाने हेतु कोई विशेष योजना तैयार किये जाने का प्रस्ताव है?

**योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती रत्नमाला देहरेश्वर सवनूर):** (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना से पहले देश में बेरोजगार व्यक्तियों की कुल संख्या 1987-88 में एनएसएसओ(43वें दौर) द्वारा कराए गए सर्वेक्षण से उपलब्ध कराई गई है। 1987-88 के एनएसएसओ अनुमानों से यथा-उपलब्ध, सामान्य सिद्धान्त स्थिति के अनुसार राज्यवार बेरोजगारी संलग्न विवरण में दी गई है (नीचे देखिए)

(ख) 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निजी और सरकारी क्षेत्रकों/दोनों में सृजित नौकरियां 1993-94 में एनएसएसओ (50वें दौर) द्वारा कराए गए पंचवर्षीक सर्वेक्षण से उपलब्ध कराई गई है। 1993-94 के एनएसएसओ अनुमानों से यथा उपलब्ध सामान्य सिद्धान्त स्थिति के अनुसार राज्यवार रोजगार संलग्न विवरण में दिए गये है। (नीचे देखिए)।

(ग) 9वीं पंचवर्षीय योजना से पहले देश में बेरोजगार व्यक्तियों की अनुमानित संख्या 1993-94 में एनएसएसओ (50वां दौर) द्वारा कराए गए पंचवार्षिक सर्वेक्षण से उपलब्ध कराई गई है। 1993-94 के एनएसएसओ अनुमानों से यथा उपलब्ध, सामान्य सिद्धान्त स्थिति के अनुसार राज्यवार बेरोजगारी संलग्न विवरण में दी गई है। (नीचे देखिए)।

(घ) गुजरात में रोजगार सृजन के लिए कोई विशेष योजना तैयार नहीं की जा रही। यद्यपि सरकार सम्पूर्ण देश में कई स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार कार्यक्रम